SHRI S. KUNDU: Sir, it is a pertinent question and you should ask the Minister to reply to it.

MR. SPEAKER: I am glad Swamiji said something. It is accepted by all. It is not a question but very wise words by Swamiji. Now, next question.

**Translation of Enactments**

+

*1083. SHRI S.C. SAMANTA:
SHRI YASHPAL SINGH:

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the progress made in the work of publishing texts of various enactments in various languages of the country and how long it will take to complete it; and

(b) the assistance or co-operation expected from States in this direction and to what extent the States are co-operating?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (M. YUNUS SALEEM): (a) (i) Two statements showing the progress made in the work of publication of the texts of Central enactments in Hindi and the various regional languages are laid on the Table of the House (Annexures 'A' and 'B'). [*Placed in Library. See* No. LT-763/69.]

(ii) The translation of Central Acts into Hindi is expected to be completed in about five years time. It is, however, difficult to say at this stage by what time the translation of Central Acts into the various regional languages will be completed.

(b) It is expected that the translation of Central Acts into the respective regional languages will be done by appropriate agencies created by the State Governments. A statement showing the names of the State Governments which have appointed Official Language (Legislative) Commissions or similar agencies for the translation of laws into the respective regional languages is placed on the Table of the House (Annexure C'). [*Placed in Library. See* No. LT-763/69.] The work of translation into Hindi is directly attended to by the Central Official Language (Legislative) Commission.

SHRI S.C. SAMANTA: What is the 'appropriate agency' in all the States? Is it uniform or there is difference in status? While in some States the Official Language Commission is functioning in some other States other organisations are functioning.

SHRI M. YUNUS SALEEM: Different agencies have been set up in different States for translating Central Acts into regional languages and they are functioning under the guidance of the Official Language Commission with the terminology approved by the Commission. That terminology has got to be adopted by all the agencies which are functioning under the Official Language Commission.

SHRI S.C. SAMANTA: Will the legal terminology used in every State by the different agencies be uniform?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): No, Sir. The responsibility of translation of Central Acts has been delegated to the State Governments so that they may evolve appropriate agencies. Some State Governments have appointed Official Language Commissions, some are doing this through their Law Department and some others have appointed committees. It is left to the State Government to decide what agency to create. That is why we have advisedly used the term "appropriate agency". Regarding terminology, the initial idea was that there should be a common terminology for all the languages in India. Lately it has been found that it is not possible, nor feasible, nor desirable to have a common terminology for all the States. Therefore, each State is given freedom to translate Central Acts into its own language, adopting the appropriate terminology according to the discretion of the agency set up there.

श्री यशपाल सिंह : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन करने वाले जो हैं उनकी क्या काबलियत रखी है, क्या क्राइटीरिया रखा है कि वह सही कर रहे हैं ? जो

अनुवाद हो रहे हैं वह सरासर गलत हो रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन का अनुवाद किया गया है उप-शिक्षा-निदेशक जब कि सही अनुवाद होना चाहिये था शिक्षा-उप-निदेशक। इस तरह से गलत ट्रांसलेशन होरहा है। यह भाषा कोई वोटों के जरिए से तो चलती नहीं है। अंग्रेजी जबान ईडियम के सहारे चल जाती है लेकिन हमारी अपनी जबानें ईडियम के सहारे नहीं चलती हैं। हमारी जबान में ग्रामर है, तर्कशास्त्र है, एक शास्त्र के अनुसार वह चल रही है जब तक कि कोई पैरेलल ट्रांसलेशन न हो तब तक कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं कि यह सही ट्रांसलेशन है ? अब तक जो ट्रांसलेशन हुए हैं उनमें से 150 शब्द ऐसे हैं जो सरासर गलत हैं, सौ फीसदी गलत हैं, तो इस गलती को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया ?

**श्री मु० यूनस सलीम** : जनाबआली, हम कोशिश यह करते हैं कि जिस जबान के अनुवाद के लिए हमको मेम्बर की जरूरत हो, उस जबान को जानने वाला कम-से-कम हाई कोर्ट के जज के स्टेटस का या हाईकोर्ट के जज के स्टेटस का न मिल सके तो कम-से-कम डिस्ट्रिक्ट जज हो, या यह कि उसकी लीगल प्रैक्टिस इतनी हो कि वह कानून की टर्मिनालाजी को अच्छी तरह से समझता हो और उस लैंग्वेज से भी उसको काफी वाकफियत हो जिसमें कि उसको अनुवाद करना है, ऐसा व्यक्ति मिल सके। हो सकता है कि बाज ट्रांसलेशंस ऐसे हों जो आनरेबल मेम्बर को पसन्द न आएं लेकिन बाई एन्ड लार्ज कोशिश यह की जा रही है कि ऐसे ट्रांसलेशन किए जायं कि जो स्टैंडर्ड हों और उसके बमूजिब हों जो कि लैंग्वेज कमीशन ने अख्तियार किए हैं।

**श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके दो अंग हैं। एक तो यह कि केन्द्रीय सरकार के जो कानून हैं और जो प्रान्तीय सरकार के हैं, एक तो उनका हिन्दी में अनुवाद होगा और दूसरे उनका प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद होगा जो क्षेत्रीय भाषाएं कही जाती हैं। तो मैं इसके सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने बताया है कि पाँच वर्ष के अन्तर्गत इनका अनुवाद हो जायगा लेकिन जो प्रगति है जिस चाल से केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकारें ट्रांसलेशन का काम कर रही हैं उसमें यह होना असंभव-सा मालूम होता है, तो क्या प्रान्तीय सरकार जो अनुवाद का काम कर रही है उसमें धीमापन इसलिए है कि केन्द्रीय सरकार उनको आर्थिक सहायता बहुत कम देती है इस काम के लिए और अभी तक कितनी आर्थिक सहायता दी है जिसके द्वारा यह काम जल्दी से जल्दी वह कर सकें ?

**श्री मु० यूनस सलीम** : जनाब यह बात सही नहीं है कि आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार से देने में कोई कमी की जा रही है। हम करते यह हैं कि जब कोई एजेंसी किसी स्टेट में अनुवाद के लिये क्रियेट की जाती है तो हम उनसे पूछते हैं कि ट्रांसलेशन के लिए उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो कुछ भी रिक्वायरमेंट वह बयान करते हैं, हम आपस में डिस्कस करने के बाद आम-तौर पर उनकी डिमांड को ऐक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए हमारी तरफ से कोई नान-कोआपरेशन नहीं है।

DR. RANEN SEN: In this question there is repeated reference to regional languages. In fact, all our Indian languages are national languages. So, this correction has to be made. Then, what has happened to the Central Government help to each and every State for the development of the languages in each State so that the States can, on their own, develop their translation work of the enactments, orders etc.? May I know how far the Government has advanced in that respect, in helping the State to develop their own languages?

SHRI M. YUNUS SALEEM: The question of development of any regional language is not within the purview of the Official Language Commission. The function of the Official Language Commission is to get the Central Acts translated into regional languages and all the Acts in the regional languages translated into Hindi. That is the limited function of the Official

Language Commission. The question of development of the regional languages is within the purview of the State Government; it is for them to see how the respective languages are to be developed.

DR. RANEN SEN : Sir, I take objection to again using the word 'regional language'. Where does he get that word from? All are Indian languages.

SHRI GOVINDA MENON: No offence is meant. They are all national languages used in different regions.

DR. RANEN SEN : Yes; that way you should say and write.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : When the Central Acts are translated into Hindi and regional languages, the clients will become more intelligent than the lawyers thus increasing the problem of unemployment. Is that one of the reasons why the process of translation is being delayed?

SHRI M. YUNUS SALEEM : It is not correct to suggest; on the contrary, our intention is that the translations may be available to the general public and they may understand what have been the legislations enacted and what is the terminology adopted by the Central Government to be used in the regional Acts.

**श्री एस० एम० जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएंगे, क्योंकि यहां तो बहुत सारे अधिनियमों की एक लिस्ट दी है जिसका ट्रांसलेशन हुआ है मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है उसका भी तर्जुमा जितनी 14-15 नेशनल लैंग्वेजेज हैं उनमें किया गया है ? इसमें उसके बारे में दर्ज नहीं है ।

**श्री मु० यूनस सलीम** : हिन्दी में कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा···

**श्री रवि राय** : हिन्दी नहीं दूसरी भारतीय भाषाओं में ?

**श्री मु० यूनस सलीम** : हिन्दी में कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा हो चुका है । अंतरिम उसको पब्लिश किया जाने वाला है । उसके बाद हम कांस्टीट्यूशन को दूसरी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट करने का काम टेक अप करेंगे ।

## मद्य-निषेध के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संकल्प

*1084. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1968 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के फलस्वरूप, कि 2 अक्टूबर 1969 से शुरू होने वाले आगामी सात वर्षों में मद्य-निषेध की नीति को पूर्णतः क्रियान्वित किया जायेगा, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) इसके बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA): (a) The All India Congress Committee which met at Goa in November, 1968 recommended seven years' phased programme for introduction of prohibition. This is under consideration.

(b) The Chief Ministers of the States are proposed to be consulted in this matter.

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : श्रीमान्, जब यह सरकार अपनी नीति बनाती है कि पूर्ण मद्य-निषेध होना चाहिए तो क्या यह आशा की जाय कि सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि न तो सरकारी भोजों में शराब परोसी जायगी न सरकार का कोई अधिकारी शराब पियेगा, न सरकार का कोई मंत्री शराब पियेगा और प्रति वर्ष दो अक्तूबर को गांधी जयन्ती के दिन सारे मन्त्री गांधी जी की